विधानसभा में डोटासरा-दिलावर और जोगाराम पटेल के बीच तीखी नोकझोंक

तीनों नेताओं के बीच पंचायत चुनाव के मुद्दे पर शुरू हुई बहस जब निजी आरोपों व टिप्पणियों पर जा पहुंची तो देखते ही देखते सदन का माहौल अखाड़े जैसा बन गया

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के समय सदन अखाड़ा बन गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सत्ता पक्ष के मंत्रियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके चलते सदन में कई बार हंगामे की स्थिति पैदा हुई। डोटासरा ने जहाँ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वहीं मंत्रियों ने उनके कार्यकाल के पुराने मामलों को लेकर पलटवार किया।

बहस की शुरुआत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एसआईआर में अपनी पसंद की लिस्ट न आने के कारण पुराने ढर्रे पर चुनाव कराना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यहाँ बेईमानी नहीं कर सकी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि डोटासरा को प्रक्रिया की जानकारी नहीं है और आगामी निकाय व पंचायत चुनावों में भाजपा का ही परचम लहराएगा।

- **सदन में व्यक्तिगत हमलों का दौर तब शुरू हुआ जब जोगाराम पटेल ने बिड़ला ऑडिटोरियम के घटनाक्रम का जिक्र किया। इस पर डोटासरा ने तल्ख लहजे में कहा कि ''मेरा नाम गोविंद डोटासरा है, सांस भी निकाल लिया तो चौकड़ी भुला दूंगा।''**
- **जवाबी हमले में मंत्री पटेल ने भी कहा कि चौकड़ी भुलाना हमें भी आता है।'' इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी तो 2000 करोड़ रुपये के मिड-डे मील घोटाले का फंदा आ रहा है। डोटासरा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वे किसी भी जांच का स्वागत करते है।**

सदन में व्यक्तिगत हमलों का दौर तब शुरू हुआ जब जोगाराम पटेल ने बिड़ला ऑडिटोरियम के घटनाक्रम का जिक्र किया। इस पर डोटासरा ने तल्ख लहजे में कहा कि ''मेरा नाम गोविंद डोटासरा है, सांस भी निकाल लिया तो चौकड़ी भुला दूंगा।'' जवाबी हमले में मंत्री पटेल ने भी कहा कि चौकड़ी भुलाना हमें भी आता है।'' इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी तो 2000 करोड़ रुपये के मिड-डे मील घोटाले का फंदा आ रहा है। डोटासरा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वे किसी भी जांच का स्वागत करते हैं। उन्होंने दिलावर पर हमला बोलते हुए दावा किया कि मंत्री पर 14 केस दर्ज हैं और वे 6 मामलों में जमानत पर बाहर हैं, वरना सलाखों के पीछे होते। दिलावर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेषवश फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।

डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की लोकप्रियता से डरती है, इसलिए मदन दिलावर को उनके पीछे लगा रखा है। उन्होंने डॉ. किरोड़ी को अपना साढ़ू बताते हुए उनके प्रति सहानुभूति जताई। इसके जवाब में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि हमने आरएसएस की शाखा में राष्ट्रभक्ति सीखी है। हमारा लक्ष्य पद नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा करना है। हम पदों के पीछे नहीं भागते।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार मजदूर और किसान विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर किसानों के हितों के साथ समझौता कर रही है। जूली ने चेतावनी दी कि सत्ता और बहुमत हमेशा नहीं रहता और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी।

स्पीकर देवनानी ने श्रवण कुमार को बोलने से रोका तो विपक्ष ने किया सदन की कार्यवाही का बहिष्कार

जयपुर (विसं)। विधानसभा में गुरुवार को अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बोलने की मंजूरी रद्द करने के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा।

सभापति ने पहले श्रवण कुमार को बोलने की अनुमति दे दी, इसके बाद वे अनुदान मांगों पर बोलने लगे। इसी बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन में आए और श्रवण कुमार को बोलने से रोकते हुए कहा कि, ''मैंने पहले ही आपको आज मना किया था, आप 6 दिन से बोल रहे हैं, आपको बाद में बोलने की अनुमति दे देंगे, लेकिन आज नहीं। मैं अपने आदेशों की अवहेलना सहन नहीं करूंगा।''

- **विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही देर शाम आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ गई**
- **नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ''अनुमति देकर कांग्रेस के सदस्य की बेइज्जती की गई, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।''**

इस घटना के बाद अनुदान मांगों पर बहस जारी रही। डग विधायक कालूराम बोल रहे थे, तभी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए श्रवण कुमार के बोलने की अनुमति वापस लेने को गलत बताते हुए विधायक का अपमान बताया। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताई। जूली ने कहा कि हम आप लोगों की मेहरबानी से नहीं है। अनुमति देकर सदस्य की बेइज्जती की गई, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह से ही दादागिरी से ही हाउस चलाना है तो चला लीजिए, यह तरीका नहीं होता। इस दौरान जमकर नोकझोंक हुई।

शाम को 7:27 पर विधानसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर अनुदान मांगों पर बहस आगे बर। नाराज कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करके चले गए।

6 मार्च तक कामकाज तय

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवानी की अध्यक्षता में हुई कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में 6 मार्च तक का कामकाज तय किया गया है। विधानसभा में 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक छुट्टी रहेगी। इसके बाद 5 मार्च को विधानसभा में जन विश्वास विधेयक और राजस्थान दुकान और वाणिज्य संशोधन बिल बहस के बाद पारित होंगे, 6 मार्च को डिस्टर्ब एरिया बिल पारित होगा।

हालांकि 2 से ज्यादा बच्चों वालों को पंचायतीराज और निकाय चुनाव लड़ने की बाध्यता हटाने वाले दो बिलों के पास होने का समय अभी तय नहीं हुआ है। बुधवार को ही कैबिनेट ने दोनों बिलों को मंजूरी दी थी।

जयपुर की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी गुलाबी इलेक्ट्रिक बसें

चंडीगढ़ के बाद अब जयपुर में भी ठेके की ई-बसों में सफर करेंगे लोग

जयपुर (कासं)। गुलाबी नगर के बाशिंदे अब ठेके की इलेक्ट्रिक बस में सफर करेंगे। चंडीगढ़ के बाद अब राजधानी में पहली बार गुलाबी इलेक्ट्रिक बस दौड़ती नजर आएंगी। जेसीटीएसएल ने गुरुवार को ट्रायल के तौर पर तीन बसों की शुरूआत की है। ये 9 और 12 मीटर लम्बाई की आधुनिक संसाधनों से लैस बसें है। जयपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहर में वायु प्रदूषण कम होगा और डीजल पर होने वाला खर्च भी घटेगा। जबकि इन बसों से ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। ये बसें एक निजी कम्पनी चलाएगी, सरकार इस कम्पनी को प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेगी। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने गुरुवार को 3 दिवसीय ट्रायल शुरू किया है। आधुनिक ई-बसों की तकनीकी क्षमता, बैटरी परफॉर्मेंस और यात्री सुविधाओं की जांच की जा रही है। ट्रायल सफल रहने पर जून तक 300 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो सकती है।

जयपुर में अग्रवाल फार्म से सुबह 11 बजे पहली ई-बस रवाना हुई। बसों को शहर के प्रमुख रूटों पर चलाकर उनकी लोड क्षमता, चार्जिंग क्षमता और संचालन की व्यवहारिक स्थिति को जांचा जा रहा है। जेसीटीएसएल के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की ई-बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 1150 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं। इनमें से पहले चरण में 675 बसें आवंटित की गई हैं। जयपुर में पहले चरण में 150 बसें चलाई जाएंगी। इसके बाद 168 नई बसें और शामिल की जाएंगी। गुरुवार को 2 इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू हुआ है। शहर में बगराना और टोडी डिपो पर इन बसों के संचालन की तैयारी की गई है। शुरुआती चरण में दोनों डिपो को 75-75 बसें दी जाएंगी। जयपुर में संचालित होने वाली नई इलेक्ट्रिक बसों में पैसेंजर्स की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, ऑटोमेटिक दरवाजे और दिव्यांगजनों के लिए विशेष रैंप की सुविधा होगी। साथ ही बसों का सफर आरामदायक और शोर रहित होगा।

जयपुर में ई बसों के लिए दो जगह चार्जिंग डिपो बनाए जा रहे है। एक डिपो बगराना तो दूसरा टोडी में है। फिलहाल दोनों ही डिपो का काम अधूरा पड़ा है। बगराना के डिपो का काम मार्च में पूरा होने की संभावना है। टोडी के डिपो बनाने और सुविधाओं में कई अड़चन आ रही है।

- **जेसीटीसीएसएल ने गुरूवार से बसों का तीन दिवसीय ट्रायल शुरू किया, यह सफल रहने पर जून तक 300 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें आ सकेंगी**
- **बताया जा रहा है कि ये बसें एक निजी कम्पनी चलाएगी, सरकार इस कम्पनी को प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेगी।**

जयपुर में ई बस सेवा के संचालन को लेकर केंद्र से सहायता राशि मिलेगी, बाकी राशि राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार 9 मीटर की बस के लिए 22 तो वहीं 12 मीटर की बस के लिए 24 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेगा। जेसीटीएसएल के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह ने बसों का संचालन जीसीसी ग्रॉस कॉस्ट कांटेक्ट मॉडल पर किया जाएगा।

इसके तहत बसों की खरीद, संचालन और मेंटीनेंस निजी कम्पनी करेगी, जबकि सरकार इसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेगी। बस के संचालन में करीब 70 रुपये प्रति किमी की लागत आ रही है। फिलहाल यह तय नहीं है कि बस संचालक को प्रतिकिलोमीटर पर कितने रुपये दिए जाएंगे। बसों में जनता से लिए जाने वाला किराया जेसीटीसीएल ही तय करेगी।

'गौवंश के लिए 25 प्रतिशत बढ़ाया अनुदान'

जयपुर (विसं)। गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार गौशालाओं एवं नन्दीशालाओं को नियमित रूप से अनुदान उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार ने अनुदान राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि की है। इसके बाद भी नियमानुसार राशि में वृद्धि की गई है। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक हरलाल सहारण के पूरक प्रश्नों के जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि गौशालाओं को 9 व नन्दीशालाओं को 12 माह का अनुदान दिया जा रहा है। दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित गौवंश के लिए 12 माह सहायता राशि दी जा रही है। इससे पहले मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि चूरू में 278 गौशालाएं पंजीकृत हैं। राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 (संशोधित 2021) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016-17 से पात्र गौशालाओं में गौवंश को चारा-पानी एवं पशु आहार के लिए 270 दिवस सहायता राशि दो चरणों में दी जाती है। वर्तमान में बड़े गौवंश के लिए 50 रुपये तथा छोटे गौवंश के लिए 25 रुपये प्रतिदिन सहायता दी जा रही है।

मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि विभाग की अन्य योजनाओं के तहत भी पात्र गौशालाओं को आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता राशि देने का प्रावधान है।

सार-समाचार

जलभवन का घेराव की रणनीति बनाई

जयपुर (कासं)। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक ने 13 मार्च को जयपुर स्थित जल भवन के घेराव की चेतावनी दी है। प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह शेखावत व जिला अध्यक्ष ताराचन्द सैनी के नेतृत्व में गुरूवार को तिलक नगर स्थित कार्यालय में हुई आम सभा यह निर्णय लिया गया। कर्मचारियों का कहना था कि जलदाय विभाग के निजीकरण और ओएंडएम के विरोध में यह आंदोलन होगा। बैठक में शामिल सैकड़ों कर्मचारियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल कर्मचारियों के अधिकारों की लडाई नहीं, बल्कि जनता के जल अधिकारों की रक्षा का संघर्ष है। जलदाय विभाग का निजीकरण सीधे-सीधे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा पर हमला है जनता को महंगा और असुरक्षित पानी देने की साजिश है। वर्षों से खड़ी सार्वजनिक व्यवस्था को पूंजीपतियों के हवाले करने का षड्यंत्र है। जलदाय इंटक स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है कि जनता के पानी को मुनाफे की वस्तु नहीं बनने दिया जाएगा। यदि सरकार व विभाग ने निजीकरण और ओएंडएम का फैसला वापस नहीं लिया, तो यह आंदोलन और अधिक उग्र, व्यापक एवं निर्णायक रूप लेगा।

कुलपति की नियुक्ति पर जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति पद पर नियुक्ति से जुडे मामले में विवि के चांसलर, रजिस्ट्रार और राज्य सरकार सहित कुलपति डॉ. सुमंत व्यास को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. आरके बघेरवाल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विवि के चांसलर ने विवि में कुलपति नियुक्ति के लिए गत 23 अप्रैल को सर्च कमेटी का गठन किया। वहीं गत तीन मई को कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। वहीं चार सितंबर को डॉ. सुमंत व्यास को कुलपति पद पर नियुक्ति दी गई। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार विवि से जुडा कोई भी व्यक्ति सर्च कमेटी में शामिल नहीं हो सकता। वहीं कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए दस साल का शिक्षण अनुभव जरूरी है। याचिका में कहा गया कि सर्च कमेटी का अध्यक्ष त्रिभुवन शर्मा को बनाया गया, जबकि वे विवि के पशु पोषण विभाग के प्रोफेसर व हैड रख चुके हैं। इसके अलावा डॉ. सुमंत व्यास के पास दस साल का शैक्षिणक अनुभव नहीं है। ऐसे में जब सर्च कमेटी का गठन ही गलत है तो उसकी ओर से किया गया चयन भी अपने आप में गलत है। वहीं डॉ. सुमंत व्यास के पास तय अनुभव भी नहीं है। ऐसे में सर्च कमेटी के गठन को अवैध घोषित करते हुए कुलपति की नियुक्ति को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

पति को सजा, विवाहिता ने जान दी

जयपुर । हसनपुरा स्थित रैगर बस्ती में एक 21 वर्षीय विवाहिता ने चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। मृतका नीरू बंजारा आंधी के तागड़वाड़ा की निवासी थी और अपने पति मनीष कुमार जांगिड़ के साथ किराए के मकान में रह रही थी। पुलिस के अनुसार नीरू ने दिसंबर 2025 में अलवर निवासी मनीष कुमार जांगिड़ से प्रेम विवाह किया था। हाल ही में पति को सजा होकर जेल भेजे जाने की जानकारी मिलने पर वह अवसाद में आ गई थी। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा। जिसमें स्वयं की इच्छा से आत्महत्या करने की बात कही है। गुरुवार दोपहर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में नीरू चुन्नी के फंदे से लटकी मिली।

यूजीसी के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन

जयपुर । प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूजीसी) को लेकर जारी घमासान के बीच गुरुवार को राजधानी के शहीद स्मारक पर समर्थन में बड़ा प्रदर्शन हुआ। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी के नेतृत्व में एससी,एसटी और ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के पक्ष में हुंकार भरी। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया। जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भीड़ ने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी हल्की झड़प भी हुई। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर संगठन का झंडा लहराने लगे। जिन्हें पुलिस ने मशक्कत कर नीचे उतारा।

शून्यकाल के दौरान विधायक ने की फोन पर बात

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उस समय हलचल की स्थिति बन गई, जब हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल सदन की कार्यवाही के बीच मोबाइल फोन पर बात करते नजर आए। उस समय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आसन पर मौजूद थे और सदन की कार्यवाही जारी थी। शून्यकाल के दौरान जब विभिन्न मुद्दों पर सदस्य अपनी बात रख रहे थे, तभी गणेशराज बंसल अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल फोन पर बातचीत करते दिखाई दिए। इसे लेकर कुछ सदस्यों ने आपस में आपत्ति भी जताई। हालांकि इस दौरान अध्यक्ष की ओर से सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। सदन की कार्यवाही के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर पहले भी समय-समय पर चर्चा होती रही है। संसदीय मर्यादा और आचार संहिता के तहत सदन में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा रही।

दुल्हन सौदेबाजी गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद लगी है कि गिरोह के कोलकाता, असम, बिहार, यूपी और झारखंड तक फैले नेटवर्क की कड़ियां जुड़ सकेंगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान पुलिस की सीआईडी अपराध शाखा विंग ने दुल्हन बेचने वाले अंतरराज्यीय सिंडिकेट के खिलाफ अपना शिकंजा करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना भंवरलाल शर्मा की गिरफ्तारी के ठीक बाद सीआईडी टीम ने एक और कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी महावीर सुथार को जयपुर के मानसरोवर स्थित भारत माता सर्किल से दस्तयाब कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर बालोतरा पुलिस की ओर से दस हजार रुपये का इनाम घोषित है।

यह पूरी कार्रवाई अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बिपिन कुमार पाण्डेय के निर्देशन में की गई। पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी ज्येष्ठा मैत्रयी के सुपरविजन में गठित टीम के प्रभारी एसआई शैलेन्द्र शर्मा व सदस्य

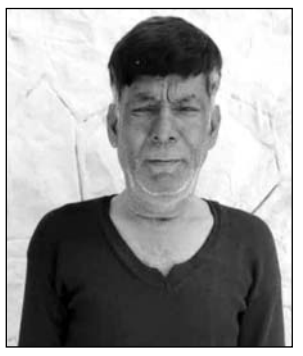

आरोपी महावीर सुथार

कांस्टेबल बृजेश शर्मा को सूचना मिली थी कि इस गैंग का सक्रिय सदस्य महावीर निवासी उनियारा टोंक जयपुर के मानसरोवर इलाके में छिपा है। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारत माता सर्किल पर जाल बिछाया और आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बालोतरा से आई थाना गिड़ा पुलिस टीम के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, महावीर सुथार उस संगठित गिरोह का अभिन्न हिस्सा है, जिसने सितंबर 2023 में बालोतरा के मगाराम को फर्जी शादी के जाल में फंसाकर 2 लाख 50 हजार की ठगी की थी। आरोपी महावीर मुख्य सरगना भंवरलाल शर्मा और रहमत खां के साथ मिलकर सौदेबाजी और पीड़ितों को ब्लैकमेल करने का काम करता था। यह आरोपी पिछले काफी समय से अपनी पहचान बदलकर पुलिस को छका रहा था।

भंवरलाल और अब महावीर सुथार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह के कोलकाता, असम, बिहार, यूपी और झारखंड तक फैले नेटवर्क की कड़ियां जुड़ सकेंगी। यह गिरोह अब तक कितने कुंवारे लड़कों को अपना शिकार बना चुका है और कितनी लड़कियों की खरीद-फरोख्त की गई है, इस संबंध में अब बालोतरा पुलिस गहन पूछताछ करेगी। मगाराम केस में अब मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी पूरी हो चुकी है।

इस कार्रवाई में सीआईडी क्राइम ब्रांच स्पेशल टीम के उप निरीक्षक शैलेंद्र शर्मा और कांस्टेबल बृजेश शर्मा की विशेष भूमिका और सहायक उप निरीक्षक शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह, कांस्टेबल नरेश कुमार का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे इनामी अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत यह बड़ी सफलता है। टीम के तकनीकी विश्लेषण और फील्ड इंटेलिजेंस के कारण ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है।

पशुधन बीमा योजना को लेकर विधानसभा में घमासान मचा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुधन बीमा योजना को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। कांग्रेस विधायक द्वारा पूछे गए सवाल पर पशुपालन मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और देखते ही देखते मामला तीखी नोकझोंक में बदल गया। आरोप-प्रत्यारोप और तंज कसने के बीच सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।

पूरक प्रश्न के दौरान हरीश चौधरी ने कहा कि पशुपालन मंत्री सीधे-साधे और सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाड़मेर में गैर संवैधानिक पावर सेंटर उन्हें काम नहीं करने देते और पाली में भी दबाव की स्थिति रहती है। बाड़मेर में प्रभारी मंत्री है, वहां पर गैर सवैधानिक ताकते काम नही करने देते हैं। पाली में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ काम नहीं करने देते हैं। ऐसे में इन सीधे-साधे मंत्री को संरक्षण दिया जाना चाहिए।

हरीश चौधरी के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री जोराराम कुमावत ने इसे गलत बताते हुए विरोध दर्ज कराया। संसदीय कार्य मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी

- **42 लाख के लक्ष्य पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव**

संस्कृति का परिचय दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि हरीश चौधरी को मंत्री पद से क्यों हटाया गया था।

हरीश चौधरी ने कहा कि उनके मूल सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा कि राजस्थान में बीमा कंपनियों को कितना प्रीमियम दिया गया है और कितने पशुपालकों को वास्तविक लाभ मिला है।

इस पर मंत्री जोराराम कुमावत ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत दो दुधारू गाय-भैंस का बीमा करने की घोषणा हुई। महंगाई राहत शिविरों में करीब 1 करोड़ 10 लाख पशुपालकों से आवेदन लिए गए, लेकिन सिर्फ 1764 पशुओं का बीमा किया गया। 23 क्लेम दावे प्राप्त हुए, जिनमें से एक भी भुगतान पशुपालकों को नहीं हुआ।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के आने के बाद 7 लाख 33 हजार रुपए का भुगतान किया गया और अब व्यापक स्तर पर योजना को लागू किया जा रहा है। पशुपालन मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 42 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 31 लाख 10 हजार 735 पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है और 16 लाख से अधिक पशुपालकों को पॉलिसी जारी कर दी गई है। शेष पशुओं का बीमा भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने पूरक सवाल उठाते हुए कहा कि मार्च तक 42 लाख का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि अब केवल एक महीना शेष है। उन्होंने सरकार से पूछा कि इतने कम समय में शेष लाखों पशुओं का बीमा कैसे किया जाएगा?

बहस के दौरान सरकारी मुख्य सचेतक भी बीच में बोलने लगे। जूली ने ऊंची आवाज में जवाब मांगा तो गर्ग ने कांग्रेस पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में विनम्रता रखनी चाहिए, मंत्री किसी के गुलाम नहीं हैं। हंगामे की स्थिति बनती देख स्पीकर ने अगला सवाल पुकार लिया और माहौल को शांत करने की कोशिश की। हालांकि पशुधन बीमा योजना को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आंकड़ों और दावों की जंग जारी रही।

इंडिया-यूएस ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

जयपुर (विसं)। भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है। गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी का आरोप है कि यह डील किसानों और लघु उद्योगों के हितों के खिलाफ है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ज्योति नगर स्थित परिसर में एकत्र हुए। उन्होंने पीएम टू कम्प्रोमाइज लिखी टी-शर्ट पहनकर और बैनर के साथ विधायकों ने अपने आवास से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। मार्च विधानसभा पोर्च तक पहुंचा, जहां विधायकों ने सीढ़ियों के बाहर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। उसके बाद काग्रेसी विधायक सदन में भी पीएम टू कम्प्रोमाइज लिखी टी शर्ट पहनकर सदन की कार्यवाही में भाग लिया। टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ट्रेड डील के बाद सोयाबीन और कपास के दामों में गिरावट आई है। उन्होंने आशंका जताई कि अमेरिका से कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात बढ़ने पर राजस्थान के किसानों को नुकसान हो सकता है।कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री से इस समझौते की शर्तों को सार्वजनिक करने और डील पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। डोटासरा ने बताया कि 9 मार्च से राजस्थान में आंदोलन की शुरुआत होगी।

केन्द्रीय मंत्री के नाम पर फर्जी ओ.एस.डी. शासन सचिवालय में पहुंचा

- **जयपुर, उदयपुर और राजसमंद में 3 दिन का वीआईपी प्रोटोकॉल और सुरक्षा मांगी**
- **सचिवालय प्रशासन की सतर्कता से फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ**

जयपुर (कासं)। राजस्थान सचिवालय में उस समय हड़कंप मच गया,जब भारत सरकार के एक केंद्रीय राज्य मंत्री के नाम पर फर्जी प्रोटोकॉल मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक शातिर व्यक्ति ने खुद को सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री का ओएसडी बता कर जयपुर, उदयपुर और राजसमंद में तीन दिन का वीआईपी प्रोटोकॉल और सुरक्षा मांगी। सचिवालय प्रशासन की सतर्कता से फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया, जिसके बाद अशोक नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है।

थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि सचिवालय के डिप्टी चीफ प्रोटोकॉल अधिकारी मानसिंह मीणा ने मामला दर्ज करवाया है कि 19 फरवरी को विभाग को एक पत्र मिला। जिसमें करण सिंह नाम के व्यक्ति ने खुद को केंद्रीय मंत्री का ओएसडी बताते हुए मंत्री के तीन दिवसीय राजस्थान दौरे का पूरा शेड्यूल भेजा था। पत्र में जयपुर में प्रवास के अलावा उदयपुर और राजसमंद (नाथद्वारा मंदिर) में दर्शन और मुख्यमंत्री से मुलाकात का भी जिक्र किया गया था।

जब प्रोटोकॉल विभाग को जब पत्र की सत्यता पर संदेह हुआ तो इसकी दिल्ली स्थित संबंधित मंत्रालय से पुष्टि की गई। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि करण सिंह नाम का कोई भी व्यक्ति मंत्री का ओएसडी है ही नहीं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आधिकारिक दौरा तय नहीं किया गया है। विभाग की जांच में पूरा यात्रा कार्यक्रम फर्जी पाए जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी पद के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस फर्जी ओएसडी की तलाश में जुट गई है।